



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287 ]  
No. 287]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 13, 2000/अग्रहायण 22, 1922  
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 2000/AGRAHAYANA 22, 1922

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2000

संख्या 47 ( आर. ई.-2000 )/1997—2002

फा. सं. 01/94/180/387/ए. एम. 01/पी. सी.-4.—का. आ. सं. 283(अ) दिनांक 31-3-97 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड-2 में यथाअधिसूचित निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 के पैरा 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक, (खण्ड-1), (आरई-00), 1997—2002 में एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. पैराग्राफ 8.75 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

“वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत ईओयू/ईपीजैड यूनिटों/नामित एजेंसियों को सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार विदेशी पर्यटकों को सादा और जड़ाऊ आभूषणों की बिक्री हेतु अन्तरराष्ट्रीय विमान पत्तनों पर शोरूम/खुदरा दुकानें बनाने की अनुमति होगी और यह निम्नलिखित शर्तों के तहत होगी :—

- (i) 60 दिनों की अवधि के बाद अन बिकी सभी आभूषण वस्तुओं का निर्यात कर दिया जाएगा अथवा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत संबंधित ईओयू/ईपीजैड/डीटीए यूनिटों/नामित एजेंसियों को लौटा दिया जाएगा।
- (ii) नीति में यथानिर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन को प्राप्त किया जाएगा।”

2. निम्नलिखित को पैरा 8.75(क) के तौर पर जोड़ा जाएगा :—

“नामित एजेंसियां अपनी शुल्क मुक्त दुकानों पर बिक्री/निर्यात हेतु नामित एजेंसियों को उनके द्वारा आपूर्ति आभूषण वस्तुओं की बिक्री/निर्यात के प्रमाण के तौर पर ईओयू और ईपीजैड/डीटीए यूनिटों को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराएंगी :—

- (i) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा बाकायदा प्रतिहस्ताक्षरित बिक्री, अनबिकी वस्तुओं की विवरणिका।
- (ii) नामित एजेंसी का प्रमाणपत्र जिसमें पार्सल विशेष की बिकी और अनबिकी वस्तुओं के मूल्य का उल्लेख हो।
- (iii) विदेश से देश में प्राप्त राशि का प्रमाणपत्र जिसमें शुल्क मुक्त दुकान पर बिकी आभूषण वस्तुओं के मूल्य का उल्लेख हो।

प्रतिपूर्ति दावा करने के उद्देश्य हेतु डीटीए यूनिट नामित एजेंसी को निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेजों सहित ऊपर क्रमांक (1) से (3) तक उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे:-

- (i) सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा सत्यापित मूल बीजक/शिपिंग बिल।
- (ii) परिशिष्ट-15घ में उल्लिखित प्रपत्र में नामित एजेंसी से प्रमाणपत्र।

3. परिशिष्ट-16घ को इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक-1 के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

4. परिशिष्ट-16ट को इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक-2 के अनुसार जोड़ा जाएगा।

5. परिशिष्ट-27 में यथा उल्लिखित शीर्षक "निर्यात संसाधन क्षेत्र" जिसमें लाइसेंसिंग प्राधिकारियों और उनके क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, को "निर्यात संसाधन क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा उसके तहत क्रमांक 33 से 39 की संबंधित प्रविष्टियाँ इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक-3 के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

6. परिशिष्ट-28क में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे:-

क. उत्पाद समूह - इंजीनियरिंग (उत्पाद कोड-61)

i) क्रमांक 256 पर निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके "न्यू मैट्रिक टूल" पढ़ा जाएगा।

ख. उत्पाद समूह - रासायन (उत्पाद कोड-62)

i) निम्नलिखित को क्रमांक-998 के बाद जोड़ा जाएगा:-

क्रमांक	विवरण	डीईपीबी दर	वैल्यू कैप
999	पिगमेंट रैड 170	8 प्रतिशत	
1000	पिगमेंट रैड 5781	6 प्रतिशत	
1001	2,4 डी एमाइन साल्ट	8 प्रतिशत	
1002	टरबुफोस टैक्नीकल 85 प्रतिशत	6 प्रतिशत	

- (ii) क्रमांक-491 के निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके "सिंगल/मल्टी कलर प्रिंटेड बुक्स, विद/विदाऊट साफ्ट/हार्ड, पी वी सी/बी ओ पीपी लेमिनेटेड जैकेट कवर" पढ़ा जाएगा।
- (iii) क्रमांक-494 के निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके "रूल्ड/अनरूल्ड/प्रिंटेड विद साफ्ट/हार्ड कवर विद या विदाऊट पीवीसी/बी ओपी पी जैकेट/लेमिनेटेड स्टेशनरी वस्तुएं जैसे एक्सरसाइज बुक/डायरी/नोटबुक/रजिस्टर/राइटिंग पैड/ड्राइंग बुक" पढ़ा जाएगा।
- (iv) क्रमांक-590 के निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके "पालीक्लोरोपीन बेस्ड एडहेसिव्स" पढ़ा जाएगा।
- (v) क्रमांक-747 के निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

"निम्न प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन एप्लीकेशन्स हेतु हाईवोल्टेज पोरसीलेन इंसूलेटर्स: क. बाल और साकेट डिस्क इंसूलेटर ख. एंटीफाग डिस्क इंसूलेटर ग. पिन टाइप इंसूलेटर घ. टंग और क्लेविस टाइप डिस्क इंसूलेटर।"

(ग) उत्पाद समूह - प्लास्टिक (उत्पाद कोड-63)

(i) निम्नलिखित को क्रमांक 145 के बाद जोड़ा जाएगा:-

क्रम सं.	विवरण	डीईपीबी दर	वैल्यू कैप
146	सल्फोनेटेड पालीथिलीन टैराफ्थलेट पावर (पालीस्टर बेस्ड रेसिन)	9 प्रतिशत	

(ii) क्रमांक-102 के निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-  
" सीकेडी/एसकेडी में के समेत एन बी आर या पीवीसी या एसबीआर से निर्मित कृत्रिम फुटवीयर"

(घ) उत्पाद समूह- चमड़ा और चमड़े के उत्पाद (उत्पाद कोड-64)

(i) निम्नलिखित को क्रमांक-31 के बाद जोड़ा जाएगा:-

क्रम सं.	विवरण	डीईपीबी दरें	वैल्यू कैप
32	चमड़ा च कृत्रिम गोल्फ ग्लोव्स	11 प्रतिशत	
33	कृत्रिम गोल्फ ग्लोव्स	11 प्रतिशत	

(ड.) उत्पाद समूह - इलैक्ट्रानिक्स (उत्पाद कोड- 83)

(i) क्रमांक-41 के निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके "टेलीफोन इंस्ट्रुमेंट (पुश बटन टेलीफोन) जिसमें उनके सीकेडी/एसकेडी शामिल हैं"

(ii) निम्नलिखित को क्रमांक-93 के बाद जोड़ा जाएगा:-

94.	साफ्टवेयर के साथ लोडेड फ्लापी डिस्कटस(इन्फार्मेशन डाटा सहित)	2 प्रतिशत	450 रूपए प्रति नग
-----	--	-----------	-------------------

(च) उत्पाद समूह - विविध मर्चे (उत्पाद कोड - 90)

(i) क्रमांक-17 के निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके "बाक्सेज/पेपर बोर्ड से निर्मित कार्टन/कोरुगेटेड कार्ड बोर्ड/लेमिनेटेड बोर्ड/क्राफ्ट पेपर-प्रिंटेड या अनप्रिंटेड, लेमिनेटेड या अनलेमिनेटेड, कोटेड या अनलेमिनेटेड, कोटेड या अनकोटेड, वार्निशड या अनवार्निशड" पढ़ा जाएगा।

7. "आईएस/आईएसओ 9000(त्र्यंखला) प्रमाणन अभिकरण" शीर्षक के तहत परिशिष्ट 32 की क्रम सं. 25 पर दिए गए हैं. इन्टरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विसिज (एशिया) प्रा.लि. के पते को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जायेगा:-

दूकान नं. 2, पहला तल,  
सूरज मल विहार,  
दिल्ली-110092  
टेलिफोन 91-11-2146659, 2148961  
टेलिफैस: 91-11-2148961  
ई-मेल: आईसीएसएपीएलडी@एनडीबी.वीएसएनएल.एनईटी.आईएन

8. परिशिष्ट-34 में निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे:-

(i) पैराग्राफ 1 के चौथी पंक्ति में "कोई भी बैंक" शब्दों के पश्चात "या संबंधित आर एल ए के पास जमा खाता रखके" शब्द और अभिव्यक्ति को जोड़ा जायेगा।

(ii) पैराग्राफ 3 के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा:-

या

(3) निम्नलिखित रूप से संबंधित आरएलए के पास जमा खाता रखा जायेगा:-

आवेदक संबंधित वेतन और लेखा अधिकारी (वाणिज्य) के नाम में बैंक/डीडी के जरिये संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास छह माह के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रत्याशित राशि जमा करेगा।

प्रारम्भ में, यह राशि मुख्य शीर्ष 8443 सिविल जमा, 114 निर्यात व्यापार जमा के तहत सार्वजनिक खाते में जमा की जायेगी जिसे लाइसेंस शुल्क के लिए समायोजित किया जा सकता है। लाइसेंसिंग प्राधिकारी आवेदन शुल्क जमा करते समय "निर्यात व्यापार जमा की ब्राड शीट" में समायोजन करेगा और "निर्यात व्यापार जमा" शीर्ष से आवेदन शुल्क के मूल्य को कांटा क्रेडिट द्वारा राजस्व मुख्य शीर्ष-1453 विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन, 103-निर्यात लाइसेंसिंग आवेदन शुल्क" में डेबिट करेगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी ऐसी सभी ट्रांसेक्शन्स (जैसे सार्वजनिक खाते से राजस्व खाते आदि में हस्तांतरित राशि) के ब्यौरे संबंधित वेतन और अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो खातों के मासिक समेकन में समायोजन प्रविष्टि करेगा। ट्रांसेक्शन की एक प्रति सामंजस्य प्रयोजन के लिए संबंधित फर्म को भी भेजी जाएगी।

टिप्पणी: जो फर्म भुगतान की इस पद्धति को अपनाना चाहती है, तो उसे प्रतिष्ठित और नियमित आवेदक होना चाहिए जिसने पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान कम से कम 25 आवेदन/ट्रांसेक्शन्स किए हों। इस योजना के तहत न्यूनतम जमा 1,00,000/-रु. में कम नहीं होगा। जमा की प्रतिपूर्ति के संबंध में बाद के सभी भुगतान पे आर्डर के माध्यम से सीपीएओ के संबंधित कार्यालय को किया जायेगा। जब तक फर्म के खाते में जमा शेष रहेगा तब तक किसी लाइसेंस के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। लेखा-परीक्षा द्वारा बाद में पता लगाये गये कम प्रभारों सहित डीजीएफटी के साथ किए गए जमाकर्ता के ट्रांजेक्शन से संबंधित सभी प्रभारों को जमाकर्ता के खातों से डेबिट किया जायेगा। इसी प्रकार, शुल्क के अधिक भुगतान या गलत भुगतान को इस परिशिष्ट में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार वापिस किया जायेगा।

9. परिशिष्ट 35 में "चण्डीगढ़" शीर्ष के अन्तर्गत क्रम सं. 145 पर निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा, जिसमें आवेदन शुल्क के लिए भुगतान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं की सूची दी गई है-

145. एस.सी.ओ. 293, सैक्टर 35 डी

10. परिशिष्ट-51ख में राज्य शीर्ष दिल्ली के तहत क्रम सं. 6 के पश्चात निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा:-

7. दिल्ली चैम्बर आफ कामर्स

49, रानी झांसी रोड,

नई दिल्ली-110055

टेलिफोन- 3616421-24/3515828

ई-मेल: डीसीसीएनडी@एनडीए.वीएसएनएल.एनईटी.आईडन

11. परिशिष्ट-16झ को इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक-4 के तौर पर जोड़ा जाएगा

### शुद्धिपत्र

1. सार्वजनिक सूचना संख्या 11, दिनांक 1 जून, 2000 द्वारा शामिल की गई क्रम सं० 987 पर डी ई पी बी प्रविष्टि के तदनुरूप निर्यात उत्पाद के विवरण को ठीक करके “टेट्रा एन-बुटाइल टाटानेट मोनोमर (न्यूनतम शुद्धता 99 प्रतिशत)” पढ़ा जाएगा।
2. सार्वजनिक सूचना सं० 37, दिनांक 19 अक्टूबर, 2000 के अनुलग्नक-2 के रूप में यथा अधिसूचित, परिशिष्ट 16ज की मद सं० 4 की क्रम सं० 10 पर उल्लिखित “पैराग्राफ 17.25” और “क्रम सं० 8 उपर्युक्त” शब्द और अभिव्यक्ति को संशोधित करके क्रमशः “पैराग्राफ 9.40” और “क्रम सं० 9 उपर्युक्त” पढ़ा जाएगा।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट - 16 घ  
विकास आयुक्त का कार्यालय  
————निर्यात संसाधन क्षेत्र  
वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार

दिनांक .....

सेवा में

मैसर्स.....

.....

विषय:- .....के विनिर्माण हेतु 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख स्कीम के  
अन्तर्गत अनुमति हेतु निर्यातोन्मुख यूनिट का आवेदन पत्र ।

संख्या.....ई पी जैड.....दिनांक.....

प्रिय महोदय/महोदया,

उपर्युक्त आवेदन पत्र के सन्दर्भ में सरकार/विकास आयुक्त नये उद्यमों की  
स्थापना हेतु आपके लिए सयंत्र और मशीनरी के अधिकतम उपयोग के आधार पर नीचे  
विनिर्दिष्ट क्षमताओं तक के निम्नलिखित मदों के निर्माण हेतु.....राज्य में  
..... निर्यात और आयात नीति/प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) 1997-2002 में  
यथाविनिर्दिष्ट निर्यातोन्मुख यूनिट स्कीम के प्रावधानों के अधीन और अनुमत सभी  
सुविधाओं और अधिकारों का विस्तार करते हैं ।

निर्माण की मद/मदें

यूनिट

वार्षिक क्षमता

उपर्युक्त अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अलावा अनुलग्नक में निर्धारित शर्तों के  
अधीन होगी ।

- (1) यूनिट को अस्वीकृत माल को छोड़कर अपने सम्पूर्ण उत्पादन का निर्यात करना  
होगा और वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि  
के लिए निर्यात और आयात नीति के प्रावधानों के अनुसार घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में  
बेचना होगा । इस प्रयोजन के लिए यूनिट संबंधित विकास आयुक्त को प्रक्रिया

पुस्तक (खण्ड-1) में यथानिर्धारित एक विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करें। यूनिट मौजूदा लघु और क्षेत्रीय नीति के तहत आरक्षित मर्चों के विनिर्माण के संबंध में उस समय लागू औद्योगिक नीति को ध्यान में रखते हुए घरेलू बाजार के लिए उत्पादन हेतु बाण्ड या अपना ई ओ यू स्तर का नवीकरण करेगा।

- (2) यह नोट किया गया है कि ई सी यू योजना के अधीन फार्मूले के अनुसार परिकल्पित निर्यात के प्रतिशत के रूप में अर्जित निवल विदेशी मुद्रा का उत्पादन प्रारम्भ होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के दौरान..... परिकल्पित किया गया है। तथापि, यूनिट को निर्यात आयात नीति के परिशिष्ट-1 में दिए गए एन एफ इ पी के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करना होगा और ऐसा करने पर यूनिट के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
  - (3) यह नोट किया गया है कि आपको प्रस्तावित परियोजना के लिए..... रुपये के मूल्य की आयातित पूंजीगत वस्तुओं की जरूरत है।
  - (4) यह नोट किया है कि अपने पांच वर्षों में.....अमेरिकी डॉलर के निर्यात कारोबार की परिकल्पना की है। तथापि, यूनिट को निर्यात आयात नीति के परिशिष्ट-1 के अनुसार न्यूनतम निर्यात निष्पादन को प्राप्त करना होगा और ऐसा न कर पाने पर यूनिट के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
3. यह अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध है इस अवधि के भीतर आपको परियोजना को कार्यान्वित करना होगा और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना होगा और उक्त अवधि के अंत से पूर्व वैधता अवधि में वृद्धि करने के लिए यदि आवेदन नहीं किया जाता तो यह अनुमति पत्र स्वतः ही रद्द हो जाएगा। जैसे ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाता है तो इस आशय की सूचना संबंधित ई पी जैड /एफ टी जैड के विकास आयुक्त और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को दी जाएगी और इसके बारे में वाणिज्य मंत्रालय(ई पी अनुभाग)को भी सूचित करना होगा।
4. आपसे अनुरोध है कि आप 45 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अर्थात् ..... को उपर्युक्त शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करें।



5. अनुमोदन पत्र की शर्तों में संशोधन/परिवर्तन या इसकी वैधता अवधि में वृद्धि के लिए किया जाने वाला सभी भावी पत्राचार यदि अपेक्षित हो अधोहस्ताक्षरी या जहां विकास आयुक्त को शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया गया है, वाणिज्य मंत्रालय के साथ किया जाए ।

भवदीय,

विकास आयुक्त

ई पी जैड

प्रतिलिपि:-

1. ....मंत्रालय/विभाग (ए एम)
2. वाणिज्य मंत्रालय (ई पी सैक्शन)
3. वाणिज्य मंत्रालय (कम्प्यूटर डाटा सैल)
4. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ।
5. विकास आयुक्त (एस एस आई)
6. निदेशक (सीमाशुल्क), नार्थ ब्लॉक
7. औद्योगिक निदेशक, सरकार (राज्य)
8. संयुक्त नियंत्रक, ई सी विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई ।
9. संयुक्त/उप/सहायक नियंत्रक, ई सी विभाग भारतीय रिजर्व बैंक ।
10. अवर सचिव, ई ओ यू सैक्शन, एस आई ए, डी आई पी और पी, नई दिल्ली
11. डाटा यूनिट: प्रस्तावित निवेश आवेदन अनुसार

क. भूमि

ख. इमारत

ग. मशीनरी

1. स्वदेशी

2. आयातित

घ. प्रस्तावित स्टाफ

12. स्टॉक फाइल

क्या मामले पर 100 प्रतिशत निर्यातान्मुख उद्यमों हेतु अनुमोदनों के बोर्ड द्वारा उसकी..... को..... हुई मीटिंग में मद संख्या..... के रूप में विचार किया गया था

विकास आयुक्त

.....ई पी जैड

## अनुलग्नक-2

## परिशिष्ट 16-ट

सं.  
भारत सरकार  
निर्यात संसाधन क्षेत्र

सं.-----

सेवा में

मैसर्ज-----

-----  
-----

विषय: -----एस ई जैड पर यूनिट स्थापित करने की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपके दिनांक-----के आवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कार्यकलाप करने हेतु निर्यात-आयात नीति और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1(1997-2002) में उल्लिखित प्रावधानों के तहत-----एस ई जैड पर यूनिट स्थापित करने की मंजूरी से अवगत कराने का निदेश हुआ है।

कार्यकलाप

यूनिट

वार्षिक क्षमता/कारोबार

2. यह अनुमोदन आपके द्वारा अपने परियोजना आवेदन में दिए गए ब्यौरों पर आधारित है और निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- i) यूनिट अपने उत्पादन/माल/सेवाओं का निर्यात पाँच वर्ष की अवधि के लिए आयात निर्यात नीति के प्रावधानों के अनुसार करेगा। यूनिट अपने एस ई जैड स्टेटस या डिबान्ड का बाद में नवीकरण करवा सकता है।
- ii) यूनिट को निर्यात आयात नीति, प्रक्रिया पुस्तक में यथा निर्धारित निर्यात की प्रतिशतता (एन एफ ई पी) के रूप में सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन

प्राप्त करना होगा, ऐसा न करने पर इसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

- iii) आयात/निर्यात के लिए निषेधात्मक सूची में सूचीबद्ध मदों को छोड़ कर सभी मदों आयात/स्थानीय खरीद की अनुमति होगी।
- iv) अनुमोदन पत्र जारी किए जाने के तीन महीने की अवधि के भीतर आबंटित प्लाट/एस डी एफ का कब्जा लेना होगा और फैक्टरी भवन का निर्माण/परियोजना का कार्यान्वयन अगले छः महीनों के भीतर करना होगा।

3. अनुमोदन पत्र में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने लिए आपको अधोहस्ताक्षरी के साथ निर्धारित प्रपत्र (प्रक्रिया पुस्तक(खण्ड-1) परिशिष्ट 16-ठ) में विधिक करार करना होगा।

4. आपसे अनुरोध है कि इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर उपर्युक्त शर्तों की पुष्टि करें। ऐसा न कर पाने की स्थिति में ऐसा मान लिया जाएगा कि आप परियोजना के कार्यान्वयन में इच्छुक नहीं हैं।

5. अनुमोदन पत्र स्वीकृत कार्यकलापों के शुरू करने के लिए जारी पत्र की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध होगा और यदि उक्त अवधि की समाप्ति से पहले अनुमोदन पत्र की वैधता को बढ़ाने के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता है तो यह अनुमोदन पत्र स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।

6. जैसे ही, व्यावसायिक उत्पादन/व्यापारिक लेन-देन शुरू हो तो इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाए।

7. अनुमोदन पत्र की शर्तों में संशोधनों/परिवर्तनों अथवा इसकी वैधता अवधि के लिए यदि आवश्यक हो तो भविष्य में सभी पत्र व्यवहार आदि अधोहस्ताक्षरी के साथ किया जायेगा।

भवदीय,

(विकास आयुक्त)

.....एस ई जैड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. आवेदन पत्र तथा परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति सहित सीमा शुल्क क्षेत्र के सहायक आयुक्त।
2. आवेदन पत्र और परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति सहित वाणिज्य मंत्रालय, ई पी जैड अनुभाग।
3. संयुक्त नियंत्रक, विनिमय नियंत्रण विभाग, आर बी आई, केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई (विदेशी/अप्रवासी भारतीय निवेशों में शामिल परियोजनाओं के मामले में)
4. निदेशक (सीमाशुल्क), सी बी ई सी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

अनुलग्नक-3निर्यात संसाधन क्षेत्र/विशेष आर्थिक जोन

33.	विकास आयुक्त/ संयुक्त विकास आयुक्त/उप विकास आयुक्त/सहायक विकास आयुक्त अंधेरी (ईस्ट)मुम्बई-400096	सीप्रोजोन मुम्बई फैक्स-022-8291385 ई-मेल: डी सी सीपज @ बॉम. 5.वी एस एन एल. नैट. इन	सान्ताक्रूज एस ई जैड में स्थित यूनिट और महाराष्ट्र गोआ, दमन और द्वीव दादर और नागर-हवेली में स्थित अनुमोदित ई ओ यू
34.	विकास आयुक्त/ संयुक्त विकास आयुक्त/उप विकास आयुक्त/सहायक विकास आयुक्त गांधीधाम-कच्च	काफ्टज गांधीधाम फैक्स संख्या 02836- 52250 ई मेल: काफ्टज @ विलनेट ऑनलाईन नेट	कान्दला और सूरत एस ई जैड में स्थित यूनिट और गुजरात में स्थित अनुमोदित ई ओ यू
35.	विकास आयुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त/उप विकास आयुक्त/सहायक विकास आयुक्त नैशनल हाईवे 45, टम्बारम, चेन्नई- 600045	एम ई पी जैड चेन्नई फैक्स संख्या 044- 2368218 ई मेल: एम ई पी जैड @ वी एस एनएल. कॉम एम ई पी जैड @ एम डी 5-वी एस एन एल. नैट. इन	मद्रास एक्सपोर्ट जोन में स्थित यूनिट और तमिलनाडू, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी, माहे और यानम रहित में स्थित अनुमोदित ई ओ यू
36.	विकास आयुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त/उप विकास आयुक्त/सहायक विकास आयुक्त ककानडा, कोचीन- 682030	सैपजोन अर्नाकुलम फैक्स: 0484-422530 ई मेल: डी सी सीपज @ एम डी2. वी एस एन एल. नैट. इन	कोचीन एस ई जैड में स्थित यूनिट और केरल, कर्नाटक लक्ष्यद्वीप और माहे में स्थित अनुमोदित ई ओ यू

37.	विकास आयुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त/उप विकास आयुक्त/सहायक विकास आयुक्त डुवाडा, विशाखापतनम- 530046	वी ई पी जैड विशाखापतनम फैक्स: 0891-587352 ई मेल: वी ई पी जैड @ ए पी. एन आई सी. इन	विशाखापतनम एक्सपोर्ट प्रोसैसिंग जोन में स्थित यूनिट और आंध्रप्रदेश और यानम में स्थित अनुमोदित ई ओ यू
38.	विकास आयुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त/उप विकास आयुक्त/सहायक विकास आयुक्त, नोएडा दादरी रोड फेस-2, नोएडा 201305	लिव वेल नई दिल्ली फैक्स: 91456231, 914567276 ई मेल: डी सी एन ई पी जैड @ एन डी ए, वी एस एन एल. नैट इन	नोएडा, एक्सपोर्ट प्रोसैसिंग जोन में स्थित यूनिट और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, मध्यप्रदेश और चण्डीगढ़ में स्थित अनुमोदित ई ओ ये
39.	विकास आयुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त/उप विकास आयुक्त/सहायक विकास आयुक्त द्वितीय एम एस ओ बिल्डिंग, चतुर्थ फ्लोर, निजाम प्लेस, कलकत्ता-700020	एफ ई पी जैड कलकत्ता फैक्स: 033-2477923 ई मेल: एफ ई पी जैड @ वैब. एन आई सी. इन डी सी एफ ई पी जैड @ x 400 एन आई सी जी डब्ल्यू. एन आई सी. इन	फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसैसिंग जोन में स्थित यूनिट और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम में स्थित ई ओ यू

अनुलग्नक-4  
परिशिष्ट-16 झ

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग

राज्य सरकार द्वारा अथवा सार्वजनिक/निजी/संयुक्त क्षेत्र में विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश।

निर्यात उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से, राज्य सरकार द्वारा अथवा सार्वजनिक, निजी, संयुक्त क्षेत्र में विशेष आर्थिक जोन(एस ई जैड) स्थापित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। ऐसे प्रस्तावों पर निम्नलिखित दिशा-निर्देश लागू होंगे:

1. निजी क्षेत्र या राज्य सरकार और एक निजी एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से या केवल राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों द्वारा एस ई जैड का विकास और प्रबंधन किया जा सकता है। निजी रूप से विकसित जोनों के मामले में, निवेशक या तो भारतीय व्यक्ति, अप्रवासी भारतीय या विदेशी कम्पनियाँ हो सकती हैं।
2. सार्वजनिक/निजी/संयुक्त/राज्य क्षेत्र में एस ई जैड स्थापित करने के लिए प्रस्तावों हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
  - (i) एस ई जैड का न्यूनतम आकार 1000 हैक्टेयर से कम नहीं होगा। तथापि, एस ई जैड में परिवर्तित होने वाले मौजूदा ई पी जैड और उत्पाद विशिष्ट के एस ई जैड पर लागू नहीं होगा।
  - (ii) एस ई जैड और इसकी यूनिटों को क्षेत्र की प्लैनिंग, सीवरेज डिस्पोजल, प्रदूषण नियंत्रण और ऐसे ही कार्यों से संबंधित स्थानीय कानूनों, नियमों, विनियमनों या उपनियमों का पालन करना होगा। इन्हें आद्यौगिक और श्रमिक कानूनों तथा स्थानीय रूप से लागू होने वाले ऐसे ही अन्य कानूनों, नियमों और विनियमनों का भी अनुपालन करना होगा।
  - (iii) ऐसे एस ई जैड सुरक्षा संबंधी प्रबंध करेंगे और इन एस ई जैड में लागू कानूनों, नियमों तथा प्रक्रियाओं की सभी जरूरतों को भी पूरा करेंगे।
  - (iv) एस ई जैड योजना के अधीन अनुमोदित यूनिटों को ही इन एस ई जैड में स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।

2. अनुमोदन संबंधी प्रक्रिया:

क. सार्वजनिक/निजी/संयुक्त/राज्य क्षेत्र के एस ई जैड को स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव पर इस प्रयोजन के लिए वाणिज्य विभाग में स्थापित एक अन्तरमंत्रालीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

ख. निम्नलिखित ब्यौरों सहित परियोजना रिपोर्ट के साथ आवेदक का नाम और पता, प्रमोटर का स्तर (चाहे व्यक्ति/निजी कम्पनी/राज्य सरकार/अप्रवासी भारतीय आदि) दर्शाने वाले आवेदन (10 प्रतिशत) राज्य सरकार के मुख्य सचिव को दिए जा सकते हैं।

- (i) मौजूदा ढांचे के ब्यौरों सहित प्रस्तावित जोन का स्थान जिसे स्थापित किया जाना है,
- (ii) निकटतम समुद्री पत्तन/हवाई पत्तन/सड़क आदि से इसके क्षेत्र की दूरी,
- (iii) प्रस्तावित निवेश समेत वित्तीय ब्यौरे, परियोजना के वित्त प्रबंधन का तरीका और परियोजनाओं की व्यवहारिकता,
- (iv) विदेशी भागीदारी और लाभांशों की वापसी आदि के ब्यौरे, यदि कोई हो,
- (v) क्या जोन कतिपय विशिष्ट उद्योगों की स्वीकृति देगा अथवा यह बहु-उत्पाद जोन होगा।

4. राज्य सरकार इसे निम्नलिखित के प्रति अपने वायदे के साथ वाणिज्य विभाग, भारत सरकार को भेजेगा:

- (i) प्रस्तावित विशेष आर्थिक जोन में शामिल क्षेत्र पर्यावरण प्रतिबंधों से मुक्त है;
- (ii) आवश्यकतानुसार पानी, बिजली और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी;
- (iii) स्व-निर्मित और खरीदी गई बिजली हेतु बिजली की बिक्री पर बिजली शुल्क और कर में पूर्ण छूट;
- (iv) विशेष आर्थिक जोन के भीतर बिजली के उत्पादन, संचारण और वितरण की अनुमति देना;
- (v) घरेलू टैरिफ क्षेत्र से विशेष आर्थिक जोन की यूनिटों को माल की आपूर्ति पर राज्य बिक्री कर, चुंगी, मंडी कर, कारोबार कर और करों, शुल्क, चुंगी, लेवी से छूट;
- (vi) जोन के अन्दर यूनिटों हेतु, औद्योगिक विवाद अधिनियम और अन्य संबंधित अधिनियमों के तहत विकास आयुक्त अथवा जोन हेतु विशेषतः तैनात राज्य सरकार के अधिकारी को शक्तियां प्रदान की जाएगी तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत जोन को सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा घोषित किया जाएगा।
- (vii) राज्य कानूनों/नियमों के तहत एक जगह पर निकासी पद्धति और न्यूनतम जांच आवश्यकता।

उसके बाद, राज्य सरकार के वायदों को शामिल करने वाले प्रस्ताव को सार्वजनिक/निजी/संयुक्त/राज्य क्षेत्र विशेष आर्थिक जोन की अन्तर-मंत्रालय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

5. प्रस्ताव की मंजूरी के बाद, आवेदक को अनुज्ञापत्र जारी किया जाएगा। अनुमोदन की शर्तों को भंग करने की किसी भी स्थिति में अनुमोदन को रद्द किया जा सकता है।

6. विदेशी अप्रवासी भारतीय और विदेशी/भारतीय कम्पनियों द्वारा भूस्वामित्व/विकास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निदेश इन आर्थिक क्षेत्र जोनों की स्थापना पर भी लागू होंगे।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 13th December, 2000

**No. 47(RE-2000)/1997—2002**

**F. No. 01/94/180/387/AM01/PC IV.**—In exercise of powers conferred under Paragraph 4.11 of the Export and Import Policy 1997—2002, as notified in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. No. 283(E) dated 31-3-97, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in Handbook (Vol. 1) (RE-00), 1997—2002.

**1. Paragraph 8.75 shall be amended to read as under:-**

“EOUs/EPZ Units/Nominated Agencies authorised by Ministry of Commerce & Industry shall be permitted to set up showrooms/retail outlets at the International Airports for sale of plain and studded jewellery to foreign tourists in accordance with the procedure laid down by the Customs authorities and shall be subject to the following conditions:-

- (i) All jewellery items left unsold after a period of 60 days be exported abroad or returned back to the respective EOUs/EPZ/DTA units/Nominated Agencies authorised by Ministry of Commerce and Industry.
- (ii) The minimum value addition as prescribed in the Policy shall be achieved.”

**2. The following shall be added as paragraph 8.75 (a):-**

“The Nominated Agencies shall provide the following documents to the EOUs and EPZ/DTA Units as proof of sale/export of jewellery items supplied by them to the nominated agencies for sale/export at their Duty Free Shops:

- (i) Statement of sold, unsold items duly countersigned by the Customs Authorities.
- (ii) Certificate from the Nominated Agency indicating the value of sold and unsold items of a particular parcel.
- (iii) Foreign Inward Remittance Certificate (FIRC) indicating the value of jewellery items sold at the Duty Free Shop.

For the purpose of claiming Replenishment, the DTA unit shall submit the documents mentioned at Sl. No. (i) to (iii) above along with the following additional documents to the Nominated Agency:

- (i) Original Customs attested invoice/shipping bill
- (ii) Certificate from the Nominated Agency in the form given in Appendix-15 D”.



3. The Appendix 16 D shall be amended as per Annexure I to this Public Notice.
4. The Appendix 16 K shall be added as per Annexure II to this Public Notice.
5. The heading "Export Processing Zone" as appearing in the Appendix 27 containing the list of Licensing Authorities and their jurisdiction shall be substituted by the heading "Export Processing Zone/Special Economic Zone" and the corresponding entries from Sl. No. 33 to 39 thereunder shall be amended as per Annexure III to this Public Notice.
6. The following amendments shall be made in Appendix 28A

(A) Product Group – Engineering (Product Code 61)

- i) The description of the export product at S.No 256 shall be amended to read as "Pneumatic Tool"

(B) Product Group – Chemicals (Product Code 62)

- i) The following shall be added after S.No 998

S.No.	Description	DEPB rates	Value cap
999	Pigment Red 170	8%	
1000	Pigment Red 5781	6%	
1001	2,4 D Amine salt	8%	
1002	Turbufo Technical 85%	6%	

- (ii) The description of the export product at Sl. No. 491 shall be amended to read as "Single/Multi Colour Printed Books, with/without soft/hard, PVC/BOPP Laminated Jacket cover".
- (iii) The description of the export product at Sl. No. 494 shall be amended to read as "Ruled/Unruled/Printed with soft/hard cover with or without PVC/BOPP Jacket/Laminated stationery items like Exercise Book/Diary/Notebook/Register/Writing Pad/Drawing Book."
- (iv) The description of the export product at Sl. No. 590 shall be amended to read as "Polychloroprene Based Adhesives".
- (iv) The description of the export product at Sl. No. 747 shall be amended to read as under:-  
"High voltage porcelain insulators for transmission line applications of the following type: a) Ball and Socket Disc Insulator b) Antifog Disc Insulator, c) Pin type Insulator d) Tongue & Clevis type Disc Insulator."

(C) Product Group – Plastics(Product Code 63)

- (i) The following shall be added after Sl. No. 145:

S.No.	Description	DEPB rates	Value cap
146	Sulphonated Polyethylene Terephthalate Powder(Polyester Based Resin)	9%	

- (ii) The description of the export product at Sl. No. 102 shall be amended to read as under:-  
**"Synthetic Footwear made of NBR or PVC or SBR, including in CKD/SKD".**

**(D) Product Group – Leather and Leather Products (Product Code 64)**

- (i) The following shall be added after Sl. No. 31

S.No.	Description	DEPB rates	Value Cap
32	Leather-cum-Synthetic Golf gloves	11%	
33	Synthetic Golf gloves	11%	

**(E) Product Group – Electronics (Product Code 83)**

- (i) The description of the export product at S.No 41 shall be amended to read as "**Telephone Instrument (Push Button Telephones) including CKD/ SKD thereof**"  
(ii) The following shall be added after S.No 93

94.	Floppy Diskettes loaded with software (including information/ data)	2%	Rs. 450/ per piece
-----	---	----	--------------------

**(F) Product Group – Miscellaneous items (Product Code 90)**

- (i) The description of the export product at Sl. No. 17 shall be amended to read as "**Boxes/cartons made out of Paper Board/Corrugated Card Board/Laminated Board/Kraft Paper – Printed or Unprinted, Laminated or Unlaminated, Coated or Uncoated, Varnished or Unvarnished.**"
7. The address of **M/s. International Certifications Services (Asia) Pvt. Ltd.** as appearing at Sl. No. 25 of Appendix 32 under the heading "**List of IS/ISO 9000 (series) Certification Agencies**" shall be amended to read as under:-  
Shop No. 2, 1<sup>st</sup> floor,  
"B" Block Market,  
Surajmal Vihar,  
Delhi-110 092  
Tel. 91-11-2146859, 2148961  
Telefax: 91-11-2148961  
Email: [icsapld@ndb.vsnl.net.in](mailto:icsapld@ndb.vsnl.net.in)
8. The following amendments shall be made in the Appendix-34:-
- (i) The words and expression "**Or through running deposit account with the concerned RLA**" shall be inserted after the words "**any bank**" in the fourth line of Paragraph 1.

- (ii) The following shall be added at the end of Paragraph 3:-

OR

(3) Through running deposit account maintained with concerned RLA in the following manner:-

The applicants may deposit the anticipated amount as per their needs for six months with the concerned Regional Licensing Authority through cheque/DD in the name of concerned Pay & Accounts Officer (Commerce). Initially, this amount will be credited into public accounts under Major Head 8443-Civil Deposits, 114-Export Trade Deposits adjustable against Licence Application Fees. The licensing authority at the time of admitting the application fee will carry out an adjustment in "Broad Sheet of Export Trade Deposits" and debit the value of application fee from the Head "Export Trade Deposits" by contra credit to Revenue Head Head-1453-Foreign Trade & Export Promotion, 103-Export Licensing Application Fees". The licensing Authority may furnish the details of all such transactions (like the amount transferred from Public Accounts to Revenue Account etc.) to the Pay and Accounts Officer concerned who may carry out adjustment entry in the monthly compilation of accounts. A copy of the transactions may also be forwarded to the concerned firm for the purpose of reconciliation.

Note: The firms who want to resort to this mode of payment should be established and regular applicants having at least 25 applications/ transactions during the last licensing year. The minimum deposit under the scheme will not be less than Rs. 1,00,000/-. All subsequent payment in replenishment of the deposit will be made through Pay order in favour of the concerned office of CPAO. No licence application will be entertained/ considered so long as the firms have a deposit balance in their account. All the charges in connection with the depositor transaction with DGFT including undercharges detected subsequently in course of audit will be debited from the Depositor amounts. Likewise, any excess payment or wrong payment of fee will be refunded as per the procedure mentioned in this appendix.

9. The following shall be added at Sl. No. 145 under the head 'Chandigarh' in the Appendix 35 containing the list of branches of Central Bank of India authorised to receive payments for application fee:-

145. S.C.O. 293, Sector 35-U

10. The following shall be added in the Appendix 51B after Sl. No. 6 under the state head Delhi:-

7. Delhi Chamber of Commerce  
49, Rani Jhansi Road,  
New Delhi-110 055  
Tel. 3616421-24/3515828  
E-mail: [dccnd@nda.vsnl.net.in](mailto:dccnd@nda.vsnl.net.in)

11. The Appendix 16 I shall be added as per Annexure IV to this Public Notice.

**Corrigendum**

1. The description of the export product corresponding to the DEPB entry at Sl. No. 987 as added vide Public Notice No. 11, dated 1<sup>st</sup> June, 2000 shall be corrected to read as, "Tetra N-Butyl titanate Monomer (minimum purity 99%),"
2. The words and expressions "Paragraph 17.25" and "Sl. 8 above" as appearing at Sl. No. 10 of item No. 4 of Appendix 16 H, notified as Annexure II to Public Notice No. 37, dated 19<sup>th</sup> October, 2000 shall be amended to read as "Paragraph 9.40" and "S.No. 9 above" respectively.

This issues in public interest.

N L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade

## ANNEXURE I

## Appendix – 16 D

OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER  
 -----EXPORT PROCESSING ZONE  
 MINISTRY OF COMMERCE, GOVERNMENT OF INDIA  
 -----

Dated the-----

To,

M/S -----  
 -----

Subject: Your export oriented unit application for permission under the 100% Export Oriented Scheme for the manufacture of -----

No.-----EPZ ----- dated-----

Dear Sir/Madam/Gentlemen,

With reference to the above mentioned application, Govt./Development Commissioner is pleased to extend to you all the facilities and privileges admissible and subject to the provisions of the Export Oriented Unit Scheme as envisaged in Export Import Policy / Handbook of Procedure (Vol.I) 1997-2002 for the establishment of a new undertaking at \_\_\_\_\_ in the State of \_\_\_\_\_ for the manufacture of the following items(s) upto the capacities specified below on the basis of maximum utilisation of plant and machinery :-

Item(s) of manufacture	Unit	Annual capacity
------------------------	------	-----------------

The above permission is subject to the conditions stipulated in Annexure in addition to the following conditions: -

- (i) The unit shall export its entire production, excluding rejects and sales in the domestic tariff area as per provisions of Export and Import Policy for of period of 5 years from the date of commencement of commercial production. For this purpose the unit shall furnish the requisite legal undertaking as prescribed in the Handbook of Procedure (Vol. I) to the Development Commissioner concerned. The unit would have the option to renew its EOU status or debond for production for domestic market in the light of industrial policy in force at that time in relation to manufacture of the items reserved for small scale and sectoral policy prevailing at that point of time.
- (ii) It is noted that Net Foreign Earning as a percentage of export (NFEP) calculated as per formula given under the EOU Scheme, has been projected as ---- % during the period of five years from the date of commencement of production. However, the unit would be required to achieve the minimum stipulated level of NFEP as prescribed in Appendix – I of the Export-Import Policy, failing which the unit may be liable for penal action.
- (iii) It is noted that you require imported Capital Goods valued at Rs.-----for the proposed project.

- (iv) It is noted that you have projected export turnover of US \$----- in five years. However, the unit would achieve a minimum export performance as prescribed in Appendix - I of Export Import Policy failing which the unit may be liable for penal action.
- (3) This Letter of Permission is valid for 3 years from its date of issue with in which you should implement the project and commence commercial production and would automatically lapse if an application for the extension of validity is not made before the end of the said period. As soon as, commercial production starts an intimation to this effect should be sent to the Development Commissioner of concerned EPZ and Administrative Ministry/Departments concerned under intimation to Ministry of Commerce(EP Section).
- (4) You are requested to confirm acceptance of the above terms and condition to the undersigned within 45 days and the Administrative Ministry/Department viz-----  
-----.
- (5) All future correspondence for amendments/changes in terms and conditions of the approval letter or for extension of its validity, if required . etc may be addressed to the undersigned or Ministry of Commerce where powers have not been delegated to the Development Commissioner .

Yours faithfully,

Development Commissioner  
-----EPZ

Copy forwarded to :-

1. M/o / D/o----- (AM)
2. M/o Commerce (EOU Section )
3. M/o Commerce (Computer Data Cell)
4. D/o Scientific & Industrial Research, New Delhi
5. Development Commissioner (SSI)
6. Director (Custom), North Block
7. Director of Industries, Govt. of (State)
8. Jt. Controller, E.C. Deptt., RBI, Central Office, Bombay
9. Jt./Dy./Asstt. Controller, E.C. Deptt., RBI
10. Under Secretary, EOU Section, SIA, DIP&P, New Delhi
11. Data unit: Investment proposed as per application
  - (A) Land :
  - (B) Building :
  - (C) Machinery :
    - i. Indigenous :
    - ii. Imported :
  - (D) Staff proposed :
12. Stock file

(If the case was considered by the Board of Approvals for 100% Export Oriented Undertakings at its-----Meeting held on ----- item No.-----)

Development Commissioner

-----EPZ

## Annexure II

## Appendix-16-K

No.  
Government of India  
Export Processing Zone

No. \_\_\_\_\_

Dated the \_\_\_\_\_

To

M/s. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

SUB:- Grant of permission for setting up a unit at.....SEZ

-----

Sir,

I am directed to refer to your application dated \_\_\_\_\_ on the above subject and to convey the approval in terms of the provisions contained in Export and Import Policy and Handbook of Procedure Vol-I (1997-2002) for setting up a unit at \_\_\_\_\_ SEZ for carrying out the undermentioned activities.

Activity	Unit	Annual capacity/ turn over
----------	------	----------------------------

2. The approval is based on the details furnished by you in your project application and is subject to the following conditions:-

i) The unit shall export its production/ goods/services as per provisions of export and import policy for a period of five years . The unit would have option to renew its SEZ status or debond thereafter.

ii) The unit would be required to achieve positive net Foreign Exchange Earning as Percentage of exports (NFEP) as prescribed in the Export and Import Policy and Handbook of Procedures, failing which it would be liable for penal action.

iii) Import/local purchase will be permitted of all items except those listed in prohibited list for import/export.

iv) Possession of allotted plot/SDF will be taken within a period of 3 months of issue of approval letter and construction of the factory building/implementation of project shall be started within next six months.

3. You shall be required to enter into a Legal Agreement in the prescribed form (Appendix- 16-L of HBP (Vol.I) with the undersigned for fulfilling the terms and conditions mentioned in this LOA.

4. You are requested to confirm the acceptance of the above conditions within 45 days of the issue of this letter failing which it will be presumed that you are not interested in the implementation of the project.
5. This letter of approval is valid for three years from the date of its issue for commencement of approved activity and will automatically lapse, if an application for the extension of the validity period of this letter of approval is not made before the end of the said period .
6. As soon as, commercial production / transaction of business starts, an intimation to this effect should be sent to the undersigned.
7. All future correspondence for amendments/changes in terms and conditions of the approval letter or for extension of its validity, if required etc. may be addressed to the undersigned.

Yours faithfully,

( Development Commissioner)  
.....SEZ

Copy to:-

1. Assistant Commissioner of Zone Custom along with a copy the application and project report.
2. Department of Commerce, EPZ Section along with a copy the application and project report.
3. Joint Controller, Exchange Control Department, RBI, Central Office, Bombay (In case of projects involving foreign/NRI investments)
4. Director (Customs), CBEC, North Block, New Delhi



Annexure III  
Export Processing Zone/Special Economic Zone

33.	Development Commissioner/ Jt. Development Commissioner / Deputy Development Commissioner/Asstt. Development Commissioner Andheri (East) Mumbai- 400096	SEEPROZONE MUMBAI Fax-022-8291385 E-mail: dcseepz@bom.5.vsnl.net. in	Units situated in Santa Cruz SEZ and approved EOUs located in Maharashtra, Goa, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli
34.	Development Commissioner/ Jt. Development Commissioner/Deputy Development Commissioner/Asstt. Development Commissioner Gandhidham-Kachchh	KAFTZ GANDHIDHAM Fax No:02836-52250 E-mail:kaftz@wilnetonline. net	Units situated in Kandla and Surat SEZs and approved EOUs located in Gujarat
35.	Development Commissioner/ Jt. Development Commissioner/Deputy Development Commissioner/Asstt. Development Commissioner  National Highway 45, Tambaram, Chennai-600045	MEPZ CHENNAI Fax No:044-2368218 E-mail: <a href="mailto:mepz@vsnl.com">mepz@vsnl.com</a> , <a href="mailto:mepz@md5-vsnl.net.in">mepz@md5-vsnl.net.in</a>	Units situated in Madras Export Processing Zone and approved EOUs located in Tamil Nadu, Andaman & Nicobar Islands, Union Territory of Pondicherry, excluding Mahe and Yanam.
36.	Development Commissioner/ Jt. Development Commissioner/Deputy Development Commissioner/Asstt. Development Commissioner  Kakkanad, Cochin -682030	CEPZONE ERNAKULAM Fax:0484-422530  E-mail: dccepz@md2.vsnl.net.in	Units situated in Cochin SEZ and approved EOUs located in Kerala, Karnataka, Lakshadweep and Mahe.
37.	Development Commissioner/ Jt. Development Commissioner/Deputy Development Commissioner/Asstt. Development Commissioner Duvvada, Visakhapatnam- 530046	VEPZ VISAKHAPATNAM Fax: 0891-587352 E-mail:vepz@ap.nic.in	Units situated in Visakhapatnam Export Processing Zone and approved EOUs located in Andhra Pradesh and Yanam.
38.	Development Commissioner/ Jt. Development Commissioner/ Deputy Development Commissioner/Asstt. Development Commissioner  Noida Dadri Road, Phase-II, Noida-201305	LIVWELL NEW DELHI Fax:91 4562314, 91- 4567276 E-Mail dcnepz@nda.vsnl.net.in	Units situated in Nodia Export Processing Zone and approved EOUs located in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, Madhya Pradesh and

			Chandigarh.
39.	Development Commissioner/ Jt. Development Commissioner/Deputy Development Commissioner/Asstt. Development Commissioner 2 <sup>nd</sup> M.S.O Building, 4 <sup>th</sup> Floor, Nizam Place, Calcutta-700020	FEPZ CALCUTTA Fax:033-2477923 E-mail:fepz@wb.nic.in dc- fepz@x400.nicgw.nic.in	Units situated in Falta Export Processing Zone and EOUs situated in West Bengal, Orissa, Bihar, Assam, Arunachal Pradesh, Tripura, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Mizoram and Sikkim.

Annexure IV

APPENDIX-16-I

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY  
DEPARTMENT OF COMMERCE

**GUIDELINES FOR SETTING UP SPECIAL ECONOMIC ZONES IN THE PUBLIC / PRIVATE/ JOINT SECTOR OR BY THE STATE GOVERNMENT**

With a view to augmenting infrastructural facilities for export production it has been decided to permit the setting up of Special Economic Zone (SEZ) in the public, private, Joint sector or by State Governments.. The following guidelines will apply to such proposals:

1. SEZ can be developed and managed in the private sector or jointly by State Government and a private agency or exclusively by the State Government or their agencies. In the case of privately developed zones, the investors could be either Indian individuals, NRIs, Indian or foreign companies.
2. Proposals for setting up SEZ in the public/private/joint/State sector are required to meet the following conditions:
  - (i) Minimum size of the SEZ shall not be less than 1000 hectares. This would however, not apply to existing EPZs converting into SEZs or to product specific SEZs.
  - (ii) The SEZ and units therein will abide by local laws, rules, regulations or bye-laws in regard to area planning, sewerage disposal, pollution control and the like. They shall also comply with industrial and labour laws and such other laws/rules and regulations as may be locally applicable.
  - (iii) Such SEZ shall make security arrangements to fulfill all the requirements of the laws, rules and procedures applicable to such SEZ..
  - (iv) Only units approved under the SEZ Scheme would be permitted to be located in these SEZ.
3. **Procedure for approval:**
  - a) Proposal for establishing public/private/joint/State sector SEZ will be considered by an Inter-ministerial Committee set up in the Department of Commerce for this purpose.
  - b) Applications (10 copies) indicating the name and address of the applicant, status of the promoter (whether individual/private company/State Government/NRIs etc.) along with a project report covering the following particulars may be submitted to the Chief Secretary of the State:

- (i) Location of the proposed zone with details of existing infrastructure and that proposed to be established,
- (ii) Its area distance from the nearest Sea Port/Airport/Rail/Road head etc.
- (iii) Financial details including investment proposed, mode of financing the project and viability of the projects.
- (iv) Details of foreign equity and repatriation of dividends etc., if any.
- (v) Whether the zone will allow only certain specific industries or will be a multi-product zone.

4. The State Government shall, forward it alongwith their commitment to the following, to the Department of Commerce, Government of India:

- (i) The area incorporated in the proposed Special Economic Zone is free from environmental restrictions;
- (ii) Water, Electricity and other services would be provided as required;
- (iii) Full exemption in electricity duty and tax on sale of electricity for self generated and purchased power;
- (iv) To allow generation, transmission and distribution of power within SEZ;
- (v) Exemption from State Sales Tax, octroi, mandi tax, turnover tax and taxes, duty, Cess, levies on supply of goods from Domestic Tariff Area to SEZ units;
- (vi) For units inside the Zone, the powers under the Industrial Disputes Act and other related Acts would be delegated to the Development Commissioner or to an officer of the State Government posted exclusively for the Zone and the Zone will be declared as a public utility service under Industrial Disputes Act.
- (vii) Single point clearances system and minimum inspections requirement under State Laws/Rules.

Thereafter the proposal incorporating the commitments of the State Government will be placed before the Inter-Ministerial Committee on public/private/joint/State sector SEZ for consideration.

- 5. On acceptance of the proposal, a Letter of Permission will be issued to the applicant. The approval will be subject to cancellation in the event of any abuse or violation of the conditions of approval.
- 6. RBI guidelines on real estate ownership/development by NRI and Foreign/Indian companies, will also apply to the establishment of these SEZ.

